बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

[ऊर्जा विभाग - आपदा प्रबंधन विभाग - पर्यटन विभाग - योजना एवं विकास विभाग - संसदीय कार्य विभाग - स्वास्थ्य विभाग - विधि विभाग].

कुल अल्पसूचित प्रश्न 20

जाँच कराना।

***55 श्री सियाराम सिंह (179) (बाढ़)ः**

स्वास्थ्य विभाग :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1.क्या यह बात सही है कि राज्य में खसरा (मीजल्स) के बचाव हेतु व्यापक टीकाकरण के बावजूद राज्य के अधिकांश जिलों में खसरा के मामले सामने आ रहे हैं;

2.क्या यह बात सही है कि व्यापक टीकाकरण के बावजूद वर्ष 2025 में 79 मरीज एवं वर्ष 2026 में 07 जिलों में 11 मरीज, साथ ही पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल के इब्राहिमपुर पंचायत में 32 मरीज खसरा के पाए गए हैं;

3.क्या यह बात सही है कि टीकों की गुणवत्ता, कोल्ड चेन व्यवस्था, भंडारण, परिवहन प्रणाली तथा टीकाकरण प्रक्रिया में कमी के कारण खसरा के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है;

4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसकी जाँच कराने तथा भविष्य में इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

सुविधाओं का प्रावधान कराना।

***56 श्री तारकिशोर प्रसाद (63) (कटिहार):**

स्वास्थ्य विभाग क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
क्या यह बात सही है कि राज्य के पूर्णियाँ प्रमंडल में एकमात्र सरकार द्वारा संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पूर्णियाँ अवस्थित है लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी सुविधा नहीं रहने के कारण मरीजों को पटना या अन्य स्थानों पर ईलाज हेतु जाना पड़ता है, जिससे यह मेडिकल कॉलेज के मरीज बेहतर ईलाज नहीं करा पा रहे है, यदि हाँ तो क्या सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पूर्णियाँ में उच्च स्तरीय ईलाज हेतु सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं का प्रावधान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?

एम.आर. आई. एवं इंजीओंग्राफी की सुविधा

***57 श्री रणधीर कुमार सिंह (114) (मांझी):**

स्वास्थ्य विभाग :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -
1. क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी जिला स्तरीय एवं अनुमंडलीय अस्पताओं में एम.आर. आई. एवं इंजिओग्राफी की सुविधा उपलब्ध नही है, जिसके कारण मरीजों को सन्बन्धित जांच अस्पताल के बाहर से महंगे दर पर कराना पड़ता है;
2. क्या यह बात सही है कि हृदय, मस्तिष्क और नस सम्बन्धी बीमारियों के लिए एम.आर. आई. एवं इंजिओग्राफी जैसी जीवन रक्षक व्यवस्था उक्त अस्तपालों में नहीं होने से गरीबों का ईलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है;
3.यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एम.आर.आई. एवं इंजिओग्राफी की सुविधा राज्य के सभी जिलों अस्पतालों एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में कराने का विचार रखती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

हॉस्पीटल में लावारिस मरीजों का वार्ड बनाना

***58 श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (16) (कल्याणपुर):**

स्वास्थ्य विभाग क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के जिलों एवं अनुमंडलीय स्तर के हॉस्पीटल में लावारिस वार्ड नहीं रहने से समाज के वंचित, लावारिस मरीजों के इलाज एवं देख रेख में परेशानी होती है तथा ऐसे मरीजों को समान्य वार्ड में रखने से अन्य सभी मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार कबतक जिला एवं अनुमंडलीय स्तर के हॉस्पीटल में लावारिस मरीजों हेतु अलग वार्ड बनाकर समुचित इलाज तथा देख रेख करने का विचार रखती है?

नियुक्ति करना

***59 श्री विजय कुमार खेमका (62) (पूर्णियाँ):**

विधि विभाग :-

क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

1.क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला न्यायालय समेत बिहार के अन्य जिला न्यायालयों में APP, स्पेशल PP, GP एवं AGP का पद लंबे वक्त से रिक्त रहने के कारण न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है;

2.क्या यह बात सही है कि वर्तमान में न्यायालय में APP, स्पेशल PP, GP एवं AGP का पद पहले से अधिक हो गया है परन्तु पूर्व में उक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति हेतु जिला प्रशासन एवं जिला न्यायाधीश द्वारा भेजी गई अनुशंसा पत्र भेजें जाने के बाद पुनः अनुशंसा मंगाने हेतु कार्रवाई नहीं की गई है;

3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त खाली पदों पर नियुक्ति पुनः जिला प्रशासन एवं जिला न्यायाधीश द्वारा अनुशंसा सूची मंगाकर नियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

कैंसर डे-केयर सेंटरों के संचालन

***60 श्री आनन्द मिश्र (200) (बक्सर):**

स्वास्थ्य विभाग :-

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के शीर्षक Cancer Will touch nearly every family warns WHO के आलोक में ,क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि WHO की हालिया 'ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर' के अनुसार आगामी वर्षों में कैंसर के मामलों में तीव्र वृद्धि की चेतावनी दी गई है,

2.क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में मैमोग्राफी, पैप स्मीयर और अन्य बुनियादी स्क्रीनिंग सुविधाओं का भारी अभाव है, जिसके कारण मरीज अंतिम चरणों में अस्पताल पहुँच रहे हैं;

3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में कैंसर से होने वाली मौतों को रोकने हेतु जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी/कैंसर डे-केयर सेंटरों के संचालन तथा Oncologists की कमी को दूर करने का विचार रखती है,नहीं तो क्यों?

पारिवारिक चिकित्सा की अवधारणा वापस लाना।

*61 **श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह** (193) **(बड़हरा):**

स्वास्थ्य विभाग :-

क्या मंत्री,स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग की बैठक में सभी उम्र के लोगों की व्यापक चिकित्सा पर जोर देते हुए जनरल मेडिसीन, बेसिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स आदि विषय को शामिल कर देश के मेडिकल कॉलेजों में 'फैमिली मेडिसीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम' शुरू करने का निर्णय लिया गया हैं;

2.क्या यह बात सही है कि एम्स की सभी परिसरों/ई0एस0आई0सी0 मेडिकल कॉलेजों से प्रतिवर्ष काफी संख्या में बिहार के चिकित्सक फैमिली मेडिसीन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण कर एक बेहतर पारिवारिक चिकित्सक के रूप में तैयार हो रहे हैं;

3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कबतक विशेषज्ञ चिकित्सक की कमी के मद्देनजर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक (फैमिली मेडिसीन) का पद स्वीकृत कर पारिवारिक चिकित्सा की अवधारणा को वापस लाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

सुविधा प्रदान करना

*62 **श्री अनिल सिंह** (236) **(हिसुआ):**

स्वास्थ्य विभाग :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 1548 दिनांक 29.05.2026 द्वारा बिहार विधान मंडल के वर्त्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत एवं सेवानिवृत पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों /कर्मियों एवं पारिवारिक पेंशनर को कैशलेस चिकित्सा को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना लागू की गयी है;

2.क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त संकल्प की कंडिका (X) के अनुसरण में अभी तक मानक संचालन प्रक्रिया जारी नहीं की गयी है, जिसके कारण कैशलेस चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पा रही है;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कबतक मानव संचालन प्रक्रिया जारी कर कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

जाँच करना

***63 श्री भाई बिरेंद्र** (187) **(मनेर):**

स्वास्थ्य विभाग क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-क्या यह बात सही है कि पटना, कैमुर, बक्सर, जहानाबाद सहित राज्य के 16 जिलों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक बाह्य सेवा से सरकार द्वारा विभिन्न अस्पतालों में 100, K.V.A के साथ अन्य के K.V.A जनरेटर द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु पूर्व के संवेदकों को मात्र 850 रूपये प्रति घंटा की दर से राशि भुगतान किया गया है, परन्तु वित्तीय वर्ष 2024-25 से वर्तमान वित्तीय वर्ष में एम०/एस० कृष्णा कंस्ट्रक्शन, पटना एवं एम0/एस0 सिंह सर्विसेज, नालंदा को 100 के K.V.A के साथ अन्य K.V.A जेनेटर का मासिक किराया 1,20,762.71 के साथ 2116 रूपये प्रतिघंटा के दर से भुगतान किया जा रहा है, जिसके कारण लोकधन का करोड़ो रूपये अपव्यय हो रहा है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त वर्णित जिलों के विभिन्न अस्पतालों में जनरेटर से विद्युत आपूर्ति किये जाने की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

पशुपालकों को मुआवजा देना।

***64 श्री जिवेश कुमार** (87) **(जाले):**

आपदा प्रबंधन विभाग :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के अंतर्गत अग्निकांड जैसी प्राकृतिक आपदा में दुधारू एवं गैर-दुधारू पशुओं की क्षति पर मुआवजा केवल उन्हीं पशुओं के लिए दिया जाता है, जिनका पूर्व से सक्षम प्राधिकारी के यहां पंजीकरण उपलब्ध होता है?

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के छोटे एवं सीमांत पशुपालकों के पशुओं का विभिन्न कारणों से पंजीकरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण अग्निकांड में पशु की मृत्यु होने के बावजूद मुआवजा से वंचित रह जाते हैं?

(3) यदि उपर्युक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अग्निकांड अथवा अन्य अधिसूचित आपदा में पशु की मृत्यु होने पर संबंधित पशुपालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी की संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुआवजा स्वीकृत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

अस्पताल निर्माण करना

***65 श्री प्रमोद कुमार** (19) **(मोतिहारी):**

स्वास्थ्य विभाग :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में चिकित्सा महाविद्यालय की मंजुरी मंत्रीमंडल सचिवालय से प्राप्त कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकार के संयुक्त सचिव के पत्रांक-11(7), दिनांक-21.04.2022 को महालेखाकार को आंतरिक वितीय सलाहकार द्वारा मुंगेर एवं पूर्वी चम्पारण राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल निर्माण हेतु आधारभूत संरचना के लिए प्रति कॉलेज 603.38 करोड़ यानि 1207.36 करोड़ वितीय वर्ष 2022-23 में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके स्थल चयनित हेतु स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक251(1), दिनांक-27.04.2022 को जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को प्राप्त हुआ है।

2. क्या यह बात सही है कि उप महाप्रबंधक (परि0) बी0एम0एस0आई0सी0एस0, पटना के पत्रांक-832, दिनांक-03.05.2024 एवं पत्रांक-8257, दिनांक-13.12.2024 तथा पत्रांक-190, दिनांक-21.04.2026 द्वारा 25 एकड़ भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए जिला पदाधिकारी को पत्र दिया गया है;

3. यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त अस्पताल का निर्माण कराने का विचार रखती है ,नहीं तो क्यों?

AIIMS पटना के अनुरूप बढ़ाना

*66 **श्री गौतम कृष्ण** (77) (**महिषी**):

स्वास्थ्य विभाग :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना में कार्यरत लगभग 1,200 आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय में पिछले लगभग 10 वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि वे नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं;

2.क्या यह भी सही है कि IGIMS, पटना में आउटसोर्सिंग नर्सिंग स्टाफ को लगभग ₹20,000 तथा टेक्नीशियन को लगभग ₹15,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि समान प्रकृति के कार्य के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) पटना में आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्स को ₹36,000 एवं टेक्नीशियन को ₹35,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है;

3.यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार IGIMS, पटना के आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय की शीघ्र समीक्षा कर उसे AIIMS, पटना के अनुरूप बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ सुविधाओं को सुलभ व सस्ता बनाना।

*67 **श्री कुमार सर्वजीत** (229) (**बोधगया (अ० जा०)**):

स्वास्थ्य विभाग :-

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दिनांक-17.06.26 को प्रकाशित शीर्षक "दक्षिण के राज्यों में सरकारी अस्पतालों में इलाज का औसत खर्च मात्र 1357 रु पर बिहार में 10,553 रु" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए औसतन 10,553 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत (5,431 रुपये) से दुगुना और दक्षिण के राज्यों (औसत 1,357रुपये) से आठ गुना अधिक हैं;

2.क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा लिखी गयी दवाओं और जाँच की सुविधा के अभाव के कारण मरीजों पर इलाज का खर्च बढ़ जाता है;

3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ व सस्ता बनाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही हैं, नहीं, तो क्यों?

ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कराना

*68 **श्री विशाल प्रशांत** (196) (**तरारी**):

ऊर्जा विभाग :-

क्या मंत्री, उर्जा विभाग,यह बतलाने की कृपा करेगें किः-

1. क्या यह बात सही है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) 2010 के तहत हर घर बिजली पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित था;

2. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2026 तक हर गांव में विद्युत उपभोक्ता की संख्या काफी बढ़ जाने के कारण ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड है जिस कारण से प्रायः ट्रांसफार्मर जलने (खराब) की घटना होते रहती है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार हर गांव में 63 KVA की जगह अधिक क्षमता (100/200 KVA) वाली ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कराने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यो?

सुविधा उपलब्ध करना

*69 **श्री रजनीश कुमार** (143) (**तेघड़ा**):

स्वास्थ्य विभाग :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि जिला स्तरीय अस्पतालों में मरीज को समुचित चिकित्सा का लाभ नहीं मिल रहा है;

2.क्या यह बात सही है कि जिला स्तरीय अस्पतालों में चिकित्सकों के द्वारा समुचित इलाज न कर राजधानी स्थित एम्स, पी० एम० सी० एच०, आई जी० आई० एम० एस०

रेफर कर दिया जाता है, जिस करण एम्स, पी० एम० सी० एच०, आई जी० आई० एम० एस०, अस्पताल पर मरीजों के दबाब के कारण मरीज समुचित चिकित्सा के लाभ से वंचित रह रहे हैं;

3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जिला स्तरीय अस्पतालों के द्वारा मरीजों को पटना रेफर करने पर रोक तथा जिला स्तर पर सरकारी अस्पतालों में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ठोस उपाय कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पुल का निर्माण

*70 **श्री मनोहर प्रसाद सिंह** (67) (**मनिहारी (अ० ज० जा०)**):

ऊर्जा विभाग क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः- क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत बैदा पंचायत में महानन्दा बांध से हाल बैदा तक बन रही सड़क पर निर्माणाधीन पुल के ऊपर से 11000 वोल्ट (KV) का विद्युत तार बहुत नीचे रहने के कारण पुल का निर्माण कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बिजली तार को ऊपर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

योजना में शामिल करना

*71 **श्री मंजीत कुमार सिंह** (100) (**बरौली**):

योजना एवं विकास विभाग :-

क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1.क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत स्टेडियम निर्माण में चेंजिंग रूम, सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, शौचालय, दर्शक दीर्घा, बास्केटबॉल टर्फ, हॉकी टर्फ, बैडमिंटन कोर्ट, बॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड, हाईमास्ट लाईट इंडोर जिम, जिमनास्टिक इक्विपमेंटस आदि कार्यो को शामिल नहीं किया गया है;

2. क्या यह बात सही है कि विभाग के अंतर्गत वैसे धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण / जीर्णोद्वार की योजना शामिल नहीं है जो धार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित नहीं है, जबकि पर्यटन विभाग के द्वारा वैसे भी धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण / जीर्णोद्वार की स्वीकृति दी जाती है;

3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में स्टेडियम निर्माण में उक्त कार्यों एवं उक्त प्रकार के धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण / जीर्णोद्वार के कार्यों को शामिल कराने का विचार रखती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पद सृजन करना।

***72 श्री अजय कुमार (138) (विभूतिपुर):**

स्वास्थ्य विभाग :-

स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक-16 जून 2026 के अंक में छपी शीर्षक"आखिर क्यों नहीं सुधर रही बिहार की चिकित्सा व्यवस्था; के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के सैम्पल रजिस्टे्शन (एसआरएस रिपोर्ट-2026 के अनुसार बिहार में 67.8 प्रतिशत मौतें चिकित्सा के अभाव, गलत इलाज तथा डॉक्टरों और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की भारी कमी के कारण हो रही हैं;

2. क्या यह बात सही है कि अधिकतर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों या पारा मेडिकल स्टाफ का सृजित पद बहुत कम है; जो पद है, उनमें भी अधिकतर खाली है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकारी अस्पतालों में पद सृजित कर रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?

पढ़ाई की व्यवस्था करना।

***73 श्री रणधीर कुमार सिंह (114) (मांझी):**

स्वास्थ्य विभाग :-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -

1. क्या यह बात सही है कि प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कालेजों में फिजियोथेरेपी में पोस्ट ग्रेजुएट (पी.जी.) की पढ़ाई की व्यवस्था नही है;

2. क्या यह बात सही है कि सरकारी कालेजों में फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर (पी.जी.) की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्रों को राज्य से बाहर अथवा निजी संस्थानों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए बाध्य होना पड़ता है;

3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सभी सरकारी मेडिकल कालेजों में फिजियोथेरेपी में पोस्ट ग्रेजुएट (पी.जी.) की पढ़ाई की व्यवस्था कराना चाहती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करना

***74 श्री आनन्द मिश्र (200) (बक्सर):**

आपदा प्रबंधन विभाग :-

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आलोक में ,क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि राज्य में मानसून की बेरुखी के कारण पूरे बिहार में औसत से 52% कम बारिश दर्ज की गई है, जैसे गया में 81%, पटना में 80%, भागलपुर में 71%

और भोजपुर में 72% तक कम वर्षा हुई है, इस कारण राज्य के 20 जिलों में अब तक धान की रोपनी की शुरुआत भी नहीं हो सकी है, इससे किसानों के सामने भुखमरी और आर्थिक संकट का खतरा पैदा हो गया है;

2. यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर सकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रभावित जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए किसानों को डीजल एवं बिजली अनुदान का वितरण तथा वैकल्पिक फसल योजना को युद्ध स्तर पर लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?